MESSAGES FROM LOK SABHA

THE VICE-CHAIRMAN (MS. INDU BALA GOSWAMI): Messages from Lok Sabha; Secretary-General.

(I) The Indian Antarctic Bill, 2022.
(II) The Biological Diversity (Amendment) Bill, 2021.

SECRETARY-GENERAL: Madam, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

(I)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Indian Antarctic Bill, 2022, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 22nd July, 2022."

(II)

"I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 22nd July, 2022, has adopted the following motion regarding further extension of time for presentation of the Report of the Joint Committee of the Houses on the Biological Diversity (Amendment) Bill, 2021:-

Motion

"That this House do further extend up to the last week of Monsoon Session 2022 of the Parliament the time for presentation of the Report of the Joint Committee on the Biological Diversity (Amendment) Bill, 2021, which was extended upto the first week of the current session on a motion adopted by this House on 18 July, 2022."

I lay a copy of the Indian Antarctic Bill, 2022 on the Table.

PRIVATE MEMBERS' BILLS - *Contd.*

The Right to Health Bill, 2021 - *Contd.*

THE VICE-CHAIRMAN (MS. INDU BALA GOSWAMI): The next speaker is Shrimati Rajani Ashokrao Patil.

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल (महाराष्ट्र) **:** उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपका अभिनन्दन करती हूँ क्योंकि आप पहली बार इस आसन पर बैठी हैं। प्रो. मनोज कुमार झा जी एक महत्वपूर्ण विषय पर अपना बिल लाए हैं, मैं उस पर अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई हूँ। हमारे साथी, राकेश सिन्हा जी ने नहीं-नहीं कहते हुए पूरी की पूरी पोलिटिकल बात यहाँ पर कह दी। मैं यहाँ पर खुद का अनुभव बताना चाहती हूँ। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ पर हैं। जब मैं सात दिन पहले संसद को अटेंड करने के लिए दिल्ली आई, तब सुबह तीन बजे अचानक मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। मैडम, मैं यहाँ पर अकेली आती हूँ और फ्लैट में अकेली रहती हूँ। आप भी वहाँ पर 'ब्रह्मपुत्र' में रहती हैं और साथ वाली बिल्डिंग 'स्वर्ण जयंती डीलक्स' में मैं रहती हूँ। मैं तीन बजे सुबह बेहोश हो गई थी, क्योंकि मुझे फूड प्वाइज़निंग हो गई थी। वहाँ पर सिर्फ एक मेड और एक ड्राइवर था। मेरी गाड़ी भी घर में नहीं थी। मैंने बाद में गाड़ी मँगवाई। मैंने बोला कि मुझे किसी भी तरह से राममनोहर लोहिया अस्पताल ले चलो। मैं इतना ही बोल पाई। जब मुझे वहाँ तक लेकर गए, मुझे यह नहीं मालूम कि मुझे वहाँ तक कैसे लेकर गए, तो वहाँ पर बहुत गंदगी थी और बहुत सारे लोग थे। एक 10x10 के रूम में आठ-दस स्ट्रेचर्स लगे हुए थे और वहाँ पर एक के ऊपर एक लोग बैठे हुए थे। वहाँ पर लोग चिल्ला रहे थे, वहाँ पर एक केऑटिक सिचुएशन थी। मैं उनको बता रही थी कि मैं एक एमपी हूँ। ...(**व्यवधान**)... आप थोड़ा एम्पेथेटिक हो जाइए, मैं मरते-मरते बची हूँ। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**सुश्री इंदु बाला गोस्वामी**) : माननीय सदस्या, कृपया आप चेयर को एड्रेस कीजिए।...(**व्यवधान**)...

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : यह आठ दिन पहले की बात है। कृपया आप सुन लीजिए।...(**व्यवधान**)... मैंने डॉक्टर्स को बोला, क्योंकि वे चाय पी रहे थे, चाय पर चर्चा कर रहे थे, कोई सफाई कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, मैंने बोला कि आप चाय वगैरह की बात मत कीजिए, पहले मुझे एड्मिट करके सेलाइन लगा दीजिए, क्योंकि मैं मर रही हूँ। यह हमारी स्थिति है। मेरे कहने का मकसद सिर्फ यह है कि अगर यह हमारे साथ हो सकता है, तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि आम लोगों के साथ क्या होता होगा। बाद में फिर मुझे नर्सिंग होम लेकर गए, फिर 9 बजे के बाद डॉक्टर्स की टीम आई। तीन घंटे के बाद डॉक्टर्स की टीम आई, तीन घंटे मुझे ऐसे ही बिताने पड़े। यह मेरा खुद का अनुभव है। सिन्हा साहब, यह मेरा खुद का अनुभव है। इसमें मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रही हूँ। अगर आप चाहते हैं, तो आप वहाँ पर डॉक्टर्स से पूछ सकते हैं। मैं कुछ भी ग्लोरिफाई नहीं कर रही हूँ।...(**व्यवधान**)...

मैं दूसरा अनुभव बताना चाहती हूँ। दो दिन पहले पेपर में एक न्यूज़ आई थी।...(**व्यवधान**)... यह हँसने वाली बात नहीं है।...(**व्यवधान**)... यह आपके साथ भी हो सकता है।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**सुश्री इंदु बाला गोस्वामी**) : माननीय सदस्या, कृपया आप चेयर को एड्रेस कीजिए।...(**व्यवधान**)...

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : अगर एक महिला के साथ ऐसा होगा, तो आप हँसेंगे? ...(**व्यवधान**)... दो दिन पहले एक न्यूज़ आई थी। 21 साल की एक लड़की, जो प्रेग्नेंट थी, उसके

33 वीक्स पूरे हुए थे, वह उत्तर प्रदेश से आई थी। वह सफदरजंग हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी के लिए डॉक्टर्स से बार-बार विनती कर रही थी। डॉक्टर्स से बोल रही थी कि मुझे एड्मिट कर लीजिए, शायद मेरी डिलीवरी हो सकती है, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे एड्मिट नहीं किया। उसको बोला गया कि आप सोनोग्राफी करवाइए। सोनोग्राफी की मशीन बंद थी। वह रात भर डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट करती रही, लेकिन उसको एड्मिट नहीं किया गया। रास्ते में उसकी डिलीवरी हो गयी। साढ़े सात बजे रास्ते में ही उसकी डिलीवरी हो गई, उसकी बच्ची पैदा हो गई। आपने देखा होगा कि सभी पेपर्स में वह न्यूज़ आई थी। मैं यह प्रैक्टिकल न्यूज़ बता रही हूँ। मैं इसमें कुछ भी बढ़ा-चढ़ा कर नहीं बोल रही हूँ। मेरा क्रिटिसाइज़ करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन we have to be empathetic. हमें एम्पेथेटिक तो होना चाहिए। यह सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा है। हम इसके लिए क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पर बोलना भी नहीं चाहती थी। जब मैंने प्रो. मनोज कुमार झा जी के बिल का विषय पढ़ा, तो मैंने खुद जाकर बोला कि मैं इस विषय पर बोलना चाहती हूँ, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें मैं भी अपना कुछ अनुभव बताना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस विषय पर बोलना चाहती हूँ और अभी मैं आपकी अनुमति से इस विषय पर बोलने के लिए खड़ी हूँ। मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया। मैं सिर्फ दो-तीन चीज़ें शेयर करना चाहूँगी।

यहाँ पर कोविड का जिक्र किया गया। कोविड से हम सब जूझ रहे थे। हमने भी इस महामारी में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। हम भी 20-20 दिन हॉस्पिटलाइज़ हुए थे। जिनकी जगह पर मैं आई हूँ, जिनका उल्लेख प्रो. मनोज कुमार झा जी ने किया, राजीव सातव, मेरे छोटे भाई, वे इस महामारी में गुज़र गए। हमारे अहमद पटेल जी भी इस महामारी में गुज़र गए। जब सरकार से महामारी के संदर्भ में पूछा गया, तो हमेशा गलत आँकड़े दिए गए।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**सुश्री इंदु बाला गोस्वामी**) : माननीय सदस्य, कृपया उनको बोलने दीजिए।...(**व्यवधान**)...

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : * मैडम, मैं आपको एक दूसरी बात यह बताना चाहती हूँ कि जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन एक आंकड़ा दे रहा है, तब गवर्नमेंट दूसरा आंकड़ा दे रही है। मेरा सिर्फ एक ही सुझाव है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें सर्टिफिकेट देती है, तब उसमें आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी साहब, जिनका नाम सुनते ही आप टेबल थपथपाते हैं, अब भी इन्हें ऐसा करना चाहिए ...(**व्यवधान**)... जी, बिल्कुल करिए। ...(**व्यवधान**)... *

मैडम, यहाँ पर फिज़िकल और मेन्टल हेल्थ की बातें की गईं। मैं मनोज झा जी का अभिनंदन करना चाहती हूँ। मेन्टल हेल्थ का इश्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको इसे अलग करना चाहिए था। हम रूरल एरिया से आते हैं। मेन्टल हेल्थ का इश्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिस पर हम हमारे रूरल एरियाज़ में ध्यान नहीं देते। अगर किसी महिला को यह तकलीफ होती है, तब हम बोलते हैं कि इसे कुछ नहीं हुआ है, यह ज्यादा नखरे कर रही है, लेकिन मेन्टल हेल्थ का इश्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ...(**व्यवधान**)... मेन्टल इश्यू पर अलग से चर्चा करना आवश्यक है। ...(**व्यवधान**)... इसके साथ ही, मुझे लगता है कि मेरी ये जो बहनें हैं, इन्हें सीरियस होने की जरूरत है। यह राज्य सभा है, यहाँ हम कोई हँसने वाली बात नहीं बोल रहे हैं।

---

* Expunged as ordered by the Chair.

...(**व्यवधान**)... मैडम, इन्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दीजिए। ...(**व्यवधान**)... आप थोड़ी सहानुभूति रखिए। ...(**व्यवधान**)...

मैडम, मैं महाराष्ट्र के संबंध में एक-दो बातें और बताना चाहती हूँ। मैं महाराष्ट्र से आती हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट बीड है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर गन्ना तोड़ने का काम होता है और जब महिलाएं गन्ना तोड़ने के लिए जाती हैं, तो उन गन्ना तोड़ने वाली महिलाओं की एफिशिएन्सी बढ़े, इसलिए उनका गर्भाशय निकलवाया जाता है। इसे लेकर इंटरनेशनल मीडिया ने भी बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं। अगर गन्ना तोड़ने के लिए उनका गर्भाशय निकाला जाता है, तब वे ज्यादा एफिशिएन्टली काम करती हैं। अतः वे ज्यादा काम कर सकें, इसलिए उनका गर्भाशय निकाल देते हैं। इस पर भी हेल्थ मिनिस्टर को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। हमारे यहाँ लड़कियों के गर्भपात कराने के जो प्रमाण हैं, वे भी बीड डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा हैं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रोफेसर झा, यह इतनी बड़ी व्याप्ति है कि यह इश्यू एक घंटे में पूरा नहीं होने वाला है। ...(**व्यवधान**)... जब मैंने मुद्दे देखे, तो पाया कि हम यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे उठा सकते हैं। ...(**व्यवधान**)... मुझे लगता है कि पीएम केयर्स फंड, गंगा की लाशें, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जिन्हें हम यहाँ बोल सकते हैं। अभी माननीय सदस्य सिन्हा जी भी बोले। ...(**व्यवधान**)... जब नेहरू जी ने यह कार्य संभाला, जब नेहरू जी प्रथम प्रधान मंत्री बने, तब उन्होंने पहली बार यह किया। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**सुश्री इंदु बाला गोस्वामी**) : प्लीज़, माननीय सदस्या को बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य, प्लीज़ माननीय सदस्या को बोलने दीजिए।

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : महोदया, उन्होंने कहा कि अगर इस देश में किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो हमें आईआईटी की आवश्यकता है, आईआईएम की आवश्यकता है, हॉस्पिटल्स की आवश्यकता है। ...(**व्यवधान**)... अगर इस देश में मंदिर से भी ज्यादा कुछ चाहिए... ...(**व्यवधान**)... इस देश को खड़ा करने के लिए 70 साल में क्या किया-क्या किया, यही गूँजता रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने 70 साल में यह किया और इसीलिए आप सब लोग खड़े हैं। ...(**व्यवधान**)... यही बताकर, मैं अपनी बात को समाप्त करूँगी, धन्यवाद।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Thank you, Chairperson Madam. I don't have the luxury of rhetoric, even if I wanted to, due to paucity of time. But I would say that right to health is already a Fundamental Right. It is already an inalienable right and this has been pronounced by the hon. Supreme Court as late as July 2020. It has said that it is the duty of the State to ensure the right to health. So, when I look at this Private Member's Bill saying that this Bill is to provide for health as a Fundamental Right to all citizens, I think, that health for all or universal health coverage has already been read into Article 21. And, therefore, to have a separate Right to Health Bill, 2021, to me, makes no sense.

Now, I come to another structural defect in the Bill. The Bill, at Clause 5, mentions right to food, right to water, right to sanitation, right to therapy, right to healthcare services, right to road safety, right to occupational safety, protection, etc.

Everything is already covered under separate legislations. Bringing in more legislation or more provisions will not really solve the problem. The problem, which I completely agree with the sentiments expressed on both the sides, is that health is an issue in the country and that health has remained to be an issue since Independence, and that is because the resources available in the country for generating this kind of health infrastructure, both physical and human resources, has not been available. None can deny the fact that the life expectancy since Independence has climbed up from 33-35 to 73-75. It has been possible only because every Government has created the health infrastructure. But, at the same time, at a time when we are discussing this, the Fifteenth Finance Commission says something and I don't really agree with my friend, Rakesh Sinhaji, because the Fifteenth Finance Commission's figure as per WHO's recommendation is one doctor per 1,000 people but India currently has one for every 1,511 people. So, we are way off the mark and if I go to specialists, I think, it is far worse. If we look at the nurse to population ratio, it is 1:670 whereas the WHO norm is 1:300. I can go on and on.

The most important fact is that even till now, the out-of-pocket expenses for a household in India going towards health expenditure account is about 54 per cent, which is very, very high. Therefore, there is a need for universal health coverage and health for all. In fact, Madam, I just recently attended a Global Conference of Parliamentary Union. There, health for all was expressed as the aspiration for every global citizen, not just for Indian citizen. This has become accentuated by the fact that post-pandemic, the people have realised that none is safe until everyone is safe. Therefore, when I say that we have to ensure right to health, we have to ensure that this infrastructure, first of all, is available. How to meet this? There has been a suggestion in this Bill that it will be through a Central legislation whereas health is a State subject. I will not get into the fact whether it can be legislated Centrally because it is a State subject. Education is a State subject but a Bill relating to right to education has been passed by the Centre, enabling the States to make separate rules and spend money. But, what is important is that the health expenditure that we do is only 1.5 to 1.7 per cent even after 75 years, whereas the WHO norm is 2.5 per cent of your GDP and our own National Health Policy norm is 2.5 per cent of our GDP! I think, that is a matter of concern.

The real concern is where will the States get the money from? Where will the State resources come from? But, then, I must say that despite resource constraints, take the case of Odisha. In Odisha, we have the Biju Swasthya Kalyan Yojana which has been made into a scheme by the hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik. We are not subscribing to Ayushman Bharat because our scheme ensures health for all in a true sense. Every APL or BPL family member, whether outdoor patient or indoor patient, can walk into a Government hospital and he will get all kinds of treatment free

of cost. If he has to get service from outside the State, there are 200 hospitals which have been empanelled.

That is the ideal model I would say, but it requires resources. Not all the States could probably afford it, but this is where the Centre should move from an insurance model to a rights-based health model where every citizen of India can walk into a hospital and get free medical treatment both indoors as well as outdoors. Mind you, Ayushman is only for indoor health care services, not for outdoor services.

Now I come to a very salient point and this is relating to the fact that Manoj ji spoke about figures relating the National Family Health Survey. He talked about life expectancy. Now I come to the pandemic. If you look at the pandemic, it overwhelmed the health infrastructure of advanced countries too. We, nor any country, can provide for reserves or a redundant health infrastructure to such an extent that it can meet any pandemic, but what all of us can do, what India can do, is to be prepared for it. Follow the disaster preparedness model that we have already shown. In Odisha, we have done it. Follow a pandemic preparedness model. The whole world, currently the IMF, the World Bank and the WHO are talking about pandemic preparedness treaty. And when you talk about pandemic preparedness, we will naturally be looking into both the human infrastructure as well as the physical infrastructure. Our emphasis in policy has always been on outputs, not on outcomes, and that is the biggest bane. When we are talking about setting up of hospitals, we say, we have set up hospitals without doctors. We have set up hospitals without paramedic staff. We have set up hospitals without nurses. Now, that is why, it is important to emphasize only on outcomes. Let outcomes be the criteria of all our policies, particularly health and education, of course.

Another point which I will talk about is the responsibility or the ownership that the community can take in health-related matters. We have seen during the pandemic that community rose to the occasion, women's Self Help Groups rose to the occasion in States like Odisha to communicate ideas relating to prevention and preparedness of the first wave of the pandemic and that is most important, the preparedness aspect, and therefore, I harp on a pandemic treaty or I harp on health preparedness scheme. If you emphasize on preparedness, I am sure everything will be taken care of. Lastly while talking about the Bill, -- I do not want to use the word -- this is an umbrella legislation for which separate legislations already exist. There is no point having another Act when the basic question of supply and distribution is not addressed. You have to supply and not even stop at that, you have to distribute those. Now, both these things can happen. It has happened over a period of time so far. It is not that it has not happened in the last 75 years, but what has happened is at a very slow pace. We need to move on. We need to move very fast because health,

as I said, is already accepted as an inalienable fundamental right of every Indian citizen. Thank you.

DR. K. KESHAVA RAO (Telangana): Madam, before I really get into the Bill, let me say one thing to Mr. Patnaik. It is true that the Supreme Court had given its judgment. Hence, according to me, there is no need for this Bill. But, we have not yet passed any legislation. The States have not taken cognizance of what the Supreme Court had said. What the Supreme Court had said has not been taken cognizance of by the States. We are not under para 3 of the Constitution. Still, it continues to be a State Subject. Therefore, on a Bill like this, which aims to make 'health' a fundamental right and bring it under para 3, there is a scope for States to step in. It will then help the States. ...*(Interruptions)*... Not necessary. Not necessary at all, because we are talking here of three things. The first one is conditions, the second is funds and the third is accessibility. These three things are entirely different and fall within the domain of the States. Anyhow, I only wanted to say one thing. It is true that the Supreme Court had said and there is not much to talk about national policy. But, nonetheless, there must be.

Madam, I have born; I have the right to birth. When I have a right to birth, I must have the right to life. It is already there. You need not give it to me through legislation. So, right to life is intrinsic to right to health. These two things are intertwined. You cannot separate them. That exactly what the spirit of this Bill is. Once you agree to the first one, the second one will automatically follow. Let us understand what exactly its needs are. Today, we have the Right to Education. It is for betterment of life. You have said something about developmental activities, corporate activities and infrastructure activities. They are for the betterment of life. So, the Bill today talks, fundamentally, about how exactly life has to be.

Hon. Member tried to make the Bill comprehensive and tried to include many things in it. But, nonetheless, it does suffer with some deficiencies. It is true. You cannot expect a comprehensive Bill, because the mover of the Bill himself said that he is apprehensive whether it will be passed or not. He is apprehensive whether the Bill will be accepted by the Government. But the question is whether it is acceptable or not. The very fact you are trying to say and what this House trying to say or focused is the point that the Government must take cognizance of it and try to incorporate important points from the Bill in their policy. That is what exactly our point of view is. Therefore, I am taking it as a fundamental thing. The right to life, being part of Article 21, yet, we also wanted this as a right so that there is a scope for legislation by the States and, at the same time, the Centre can also legislate without disturbing the rights of the States. Then, Madam, you have Articles 39, 42 and 47. They are taken care of once you make this right to life a fundamental right through legislation.

There are three things. One is this. When we talk about the Bill, we talk fundamentally, because we must talk about law and talk about the spirit of the Bill. But, my learned friend from the other side wanted to talk about politics. He has a right to talk. But, let us not politicize the issue of health. The subject 'health' is something which should not be politicized or make it partisan. He mentioned about The Lancet. What The Lancet said, what advertisements The Lancet got is another matter. It has nothing to do with it, although the Chairperson might agree with what the hon. Member has said.

Before getting into the Bill, I would like to make a few points on Ayushman Bharat. Madam, Ayushman Bharat has not been fully accepted in Telangana. Telangana today has, as a policy, created eight Government medical colleges. We have promised that 50 per cent of our districts, out of 33, would have super-specialties like we have in AIIMS and NIMS. And, we identified them in 8 districts. Hon. Health Minister knows about it. We are doing it in spite of not getting funds from the Government of India. It is an obligation to the people of the State and we are doing it. And, we are doing it on our own. That is why it takes me to the funding. Funding system is something that the mover of the Bill wanted to say, though he did not stretch much on this. Madam, Clause 7 of the Bill talks about funding. That is what exactly the concern of the entire House today is. You need funds. Today, allocation in the Union Budget for health is just 1.4 per cent of the GDP! Even the Economic Survey wanted it to be 2.5 per cent to 3 per cent. And, we — at least, I personally feel — feel it is wrong; it should be 6 per cent as far as education and health is concerned, because these are the two areas which should be the concern of the Governments. They are the concern of the Governments and other things do follow, and people themselves will take them up. But, people cannot take these two things by themselves. So, the expenditure must go from 1.4 per cent of the GDP to your own promise of 3 per cent. Madam, I am talking about issues.

4.00 **P.M.**

In Clause 2, he has given definition of 'individual'. An individual, he said, means citizen of India.

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी) : माननीय सदस्य, अब आप वाइंड अप करिए। आपके पास दो मिनट बोलने का टाइम था और पांच मिनट हो गए हैं।

डा. के. केशव राव : मैडम, यही तो मुश्किल है। हेल्थ का विषय आता है, तो दो मिनट का समय हो जाता है। अगर मैं एक शब्द भी, एक सेन्टेन्स भी बिल के बाहर बोलूं, तो आप मुझे बैठा दीजिएगा और मैं बैठ जाऊंगा। सवाल क्या है - Clause 2 में definition of 'individual' is given. An individual means citizen of India. Ours is such a great country. When we talk

about right to health, health facilities and universal health care --कभी आप बात कर रहे थे; he has just gone to International Conference and even the WHO says -- this can be to anyone, it need not be a citizen of India. As long as he is living in India, he should be entitled to health care. So, Clause 2 is something to which I have an objection to.

[THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA) *in the Chair*.]

Madam, now I come to Clause 10(2). He talked very little about pollution. But there is nothing at all about pollution. But that is a problem. That is a very big problem. Pollution should be the special attention of the Minister. He is present here. I am telling you, the way Delhi is turning out to be a polluted city of the world, we must do something with regard to it. Although the Bill does not speak about pollution, there are some who spoke about it but did not give details of the same.

Then, he has talked about conditions. He has tried to attempt on conditions that are necessary and gave seven or eight conditions; they are not enough. Conditions are many; he has only hinted at them. So, let the Minister understand that 'condition' means something which comes to your view. You have with you the entire subject. The entire domain is with you. So, you understand the difficulties and then, you can bring it. So, don't just look at the Bill as such and say that these are the conditions. This is Clause 5 I am talking about.

Now, Clause 5(h) is about the Government's help that is necessary for famines and other things. I think it is such a big canvass that the Mover of the Bill wanted to bring in, but it is such a big thing that they can't be made judiciable always. There are a few subjects which cannot be made judiciable, the Government may do it. I am giving the details clause by clause. Please don't take it lightly; this is a very serious subject. Whether you accept it or not, accept the spirit of the Bill, accept the very content of the Bill. Try to see, if not today, tomorrow, in your policy formulations or when you formulate your policies, bring these things into that; the concerns of the citizens are only two, health and education. Education, you are trying to do. The moment the Opposition gets up, you think we are all opposed to your policies. That is very wrong. When you do wrong, please say 'wrong'.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, you need to conclude.

DR. K. KESHAVA RAO: But you can't tolerate this; that is another matter. I am reminding you what the importance of this Bill is. As you understand, water is the real thing. Today, something like two lakh people die every year because of water. Though it is not brought under this Bill, I want this to be included. Then, you have

sludge and septage management. About 90 per cent of deaths are due to this. That also must come in. So, sanitation and public health should come under public health care system.

Most important of all is the expenditure that we do on medical. About 61 per cent of the expenditure of an ordinary family, say, of a middle class family, is on health. And, 69 per cent of the expenditure on health by you-- the Central Government or the State Government -- is paid by the private man. It is private. So, it is we who are paying. Kindly see how much of a burden it is on the people. So, to relieve them, you must step in in a big way and see that the insurance scheme you are talking about, not just 'Ayushman', whichever insurance scheme you bring in, is for all the people or individuals. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Shri John Brittas; you have another speaker, and you have got two minutes. So, you can take two minutes. ...*(Interruptions)*...

SHRI JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, thank you very much. Me being from Kerala, which is a model State regarding the health matters, I do expect the Chair to be a little benevolent. Sir, I don't want to politicize this issue. राकेश सिन्हा जी ने बात की और चले गए। He only politicized this matter, and actually there was no need to bring in political formulations. I congratulate Shri Manoj Jha. If education can be brought as a Fundamental Right, there is no harm in bringing health, which is a cardinal issue, cardinal point, cardinal subject. Though implicitly it is part of the right to life, but health needs to be given the importance that it deserves. The biggest problem is resources. Our hon. Minister is a very straight-forward Minister. He is very genuine. He wants to do something. I know that. But he is unable to do because of lack of resources. Let us appreciate that. I will not blame him individually. The only thing is that he has to speak up. He has to tell the leadership that more allocation has to be given to the health sector.

Sir, thousands of people died without getting access to health. Even those people who got access to hospitals, they died because there was no oxygen. I don't want to remind about those days. Sir, we talk about a lot. The Ruling Party Member was very elaborate with regard to the improvements that have happened to the health sector. Sir, let me just read out one statistic. We all harp on Sri Lanka now. Now, Sri Lanka is the focus. There was a briefing by the External Affairs Minister for the leaders of all parties with regard to Sri Lanka. Sir, with regard to health, I would just point out one index. We have 1.4 hospital beds per thousand against the world average of 2.9. Sir, Sri Lanka has 3 per thousand. We all talk about Sri Lanka. There are sectors where we lag behind. We need to have more focus, more resources. Sir, if at all you

want to improve this, at least, two beds per thousand, assuming that Mansukh Sahib wants to take it two beds per thousand, for that, we need to open, at least, 5,000 more hospitals with 200 beds. Do we have the resources?

Sir, there has been a lot of talk about *Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana*. Rakesh Sinhaji was very, very kind enough to give us a lecture on that. Sir, what has happened to the allocation? The allocation has been drastically reduced. Even the allotted amount has not been spent. Let the Minister check the Economic Survey. Let him just go through the 15th Finance Commission Report. I only want the Minister to go through three-four documents. Let him not trust me. Let him think that I am trying to mislead him. Let him just go to his Economic Survey, his National Family Survey, the 15th Finance Commission and the Standing Committee Report. If he puts together these four documents, that will give the real picture of the health.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

SHRI JOHN BRITTAS: Sir, two-three minutes more. I am from Kerala. ...(*Interruptions*)... You know that. Sir, Sanjay Singhji is here. His Party has been harping on Mohalla Clinic here, and his leader, Kejriwalji, has been coming to Kerala to lecture us. Sir, 60 years back, we started these Primary Health Centres. Please ask Ushaji. There is a health centre in every village.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude. Hon. Member, please conclude. Your time is up.

SHRI JOHN BRITTAS: * ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): No personal remarks. No personal remarks. That will be examined.

SHRI JOHN BRITTAS: Sir, two-three points more. I will just conclude.

SHRI JOHN BRITTAS: Mr. Vice-Chairman, Sir, I would make two-three points more. ...(*Interruptions*)...

Sir, this is something to guide and give inputs to the Minister. The biggest problem in this country is that 70 per cent of our people depend on the private sector; only 30 per cent go to the Government sector. It is just the other way round in Kerala. In Kerala, 80 per cent of the health needs are catered to by the Government sector

* Expunged as ordered by the Chair.

and just 20 per cent by the private sector. One more thing -- during the Covid period, 95 per cent of the Covid patients were treated free of cost by the Government sector in Kerala. Just five per cent of them went to the private sector. Also, out of that five per cent, three per cent were supported by the *Karunya Subsidy Scheme*. Further, we put a ceiling ... ...(*interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please ...(*interruptions*)... Please, Rakeshji ...(*interruptions*)... Shri Brittas... ...(*interruptions*)...

SHRI JOHN BRITTAS: You were a former... ...(*interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Brittasji, please address the Chair. ...(*interruptions*)...

SHRI JOHN BRITTAS: Sir, please allow me to call out two-three statistics because I don't want any obfuscation of the statistics. Just bear with me. I am not talking about Kerala. I will leave out Kerala. I know that when I talk about Kerala it is uncomfortable for some people.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Let us conclude.

SHRI JOHN BRITTAS: Sir, please allow me two-three minutes more. It is a Private Members' day. You should be benevolent.

Sir, let us not grope in the dark. Let me make one other point here. What was the allocation made? Compared to the previous Revised Estimates, there has been hardly a 0.2 per cent increase despite the fact that the Covid pandemic broke out. Fifty lakh people died. There was a health emergency in the country. But what was the increase in the health budget? It was just 0.2 per cent. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude. ...(*Interruptions*)... Please conclude. ...(*Interruptions*)... We will examine this. ...(*Interruptions*)... We will examine this. ...(*Interruptions*)...

SHRI JOHN BRITTAS: Sir, they are interrupting me. ...(*Interruptions*)... There is one more point. When they talk about the budgetary allocation on health, just look at how they mop up the resources. They are mopping up Rs. 53,846 crore because of the four per cent cess that they are imposing on Income Tax and Corporation Tax. They are not allocating money, but they have imposed a cess on Income Tax and Corporation Tax. Again, they have imposed another cess on import duty.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude. ...(*Interruptions*)...

SHRI JOHN BRITTAS: Even then, they did not do any justice to the health sector which is plaguing. Sir, I would just wind up by saying this. The Finance Commission says that 14 per cent of the people borrow money to go to the hospitals. Every year, six crore people are plunged into poverty because they approach hospitals for their health needs. It is a shame on this country. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I will have to move on. Take 30 seconds.

SHRI JOHN BRITTAS: Sir, I am winding up. We have to think about this. We are pushing people to poverty. They have nowhere to go to fulfill their health needs. We must consider this as a Fundamental Right. I would earnestly invite the hon. Minister to visit Kerala and see what we have done.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. Dr. Fauzia Khan. ...(*Interruptions*)... No cross-talk, please.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I must, first of all, thank Prof. Manoj Kumar Jha for having brought up this subject. He has brought up not just the subject of health, but also the voices, the anguish and pains of the poor and the deprived, and not just the poor and the deprived but also the middle class, white collared population who suffer because of lack of quality healthcare. As Rajani *Tai* mentioned, even as a Member of Parliament, what she had to undergo in an emergency, I think, we have something to learn from what she spoke here. Even I have introduced a Bill in this House called 'The Universal Healthcare Bill, 2021'. As mentioned by many Members here, Article 21 says that the right to life includes the right to health. But, I think, we need to make a distinction here. We need to provide more emphasis to the right to health because without that, the entire country is suffering. Mahatma Gandhi said, "It is health that is real wealth; not pieces of gold and silver.' If the country has to enjoy real wealth, it has to be in good mental and physical health. The population of a nation can be productive only if its individuals are physically and mentally healthy. In fact, Jim Rohn has said, "Take care of your body because it is the only place you have to live." The only place where you have to live is your body. So, it should be taken care of. Unfortunately, the current healthcare system in India reflects an economic and a social gap in accessing quality healthcare and draws attention to further measures that are required to be taken by the Central Government to assure health to all its citizens. And it is very simple! The way the Right to Education Act

was brought for providing free and compulsory education to all the children of the country, the same way the right to health must be brought. If this Bill is not accepted, the Government must come in with the Bill providing free healthcare to all the citizens of India irrespective of their class, their economic status or whatever. Many of my colleagues have mentioned that the expenditure on health is only 1.4 per cent of the Gross Domestic Product. My hon. colleague, Dr. Keshava Rao, also said that it should be, at least, six per cent. I agree with him that we need to increase the expenditure on health. Unless it is done, we cannot provide the huge population of India the relief from the ills that they go through. Out-of-pocket payments are the predominant mode for financing healthcare in the country. It should not be there when 70 per cent of our population is below poverty line. Our subsidy itself indicates how poor our country is. Here, out-of-pocket expenses are so predominantly high that we need to really think about it. This is grossly unfair and exposes a large number of households to catastrophic health expenditure which has often been a contributing factor for rural and urban indebtedness, as mentioned by my colleagues. We have also spoken about the pandemic here. The pandemic has, indeed, exposed many gaps. Many of us have spoken about the way it was handled, but I would like to speak about certain acts. Certain acts were acts of nobility, were acts of human service and were acts of sacrifice. There were many people who came forward to do that. At the same time, there were drastically terrible acts of exploitation of poor patients or rich patients by the hospitals during that time who thought this is a huge opportunity to make money. What was happening was that people were dying and, at the same time, their entire economic resource was spent on these hospitals and the future generations also suffered because the complete economy of the household collapsed during the times of pandemic. We must pay attention to this because we cannot allow a country to be ruined. Whenever there is a time of emergency, hospitals come in to loot or come in to exploit people. I think there has to be an end to this by the Government. And, this can be done by a collaborative approach, aligning the existing Government schemes, policies, the interest of the payers and the providers, along with innovative partnerships. We have the Ayushman Bharat Scheme, but as Dr. Amar Patnaik has mentioned, we need to include in-patient and out-patient here. Presently, it is only for in-patient and there is no out-patient coverage. The primary healthcare must be included here.

There is one more lacuna in the system towards which I would like to draw the attention of the Minister. In the hospital, when a patient is being treated and the family member or the caregiver goes to ask the doctor what is wrong with his/her family member, the doctor gives no answer. The family member does not know what is happening to the patient, what is the diagnosis, or, what is the treatment being given. The doctors are silent. I think the doctors and the medical staff must be taught and

they must be given trainings on soft skills and ethics on what to tell about patient, what all they should be telling about the diagnostics and about the future fate of patient. All this is not told. It is hidden. I do not know why this is done. In other countries, I have not seen this happening, but this is very common particularly in our country that the medical staff feels above everything and they don't want to reveal anything to the patient's family members, which distresses them and it sometimes results in assaults on doctors and the medical staff. So, this is one of the primary issues which the Health Department must address. I feel transparency is needed. I think a record of the patient must be maintained digitally and access should be given to the family member with the required amount of privacy, but the family of the patient has the right to know what is happening and the fate of the patient. Otherwise, they come in for a shock when something wrong happens.

With every right, there is a duty attached. There cannot be rights where there are no duties and here, the duties rest with the Government. I believe that the Government must create a national public information network of hospitals. During the pandemic, we realized that we did not know where to go. Patients were wondering where to go. There were so many people working in the social field, who came up to show that this hospital has such and such facility. So, such a data must be maintained and it must be put in public domain for the people to know where they should be going when the time arises. For instance, when Rajani *thai* collapsed, I don't think the other people immediately realized or knew where they should go, and she was taken to wherever they felt it was good. So, if you have a data bank, it will be very helpful. Sir, just give me two minutes.

Then, a pricing strategy committee must be made to make sure that the citizens are not exploited financially. Even for Ayushman Bharat, you have a pricing limit fixed up. We have also seen that when the people, who are responsible for providing healthcare, neglect the patient, they are not punished. They go scot free. There has to be a penalty for that. They should be held accountable. They should be responsible in the noble work that they are doing. But, many times, we see that they are absent from their work, they do not go there regularly and the Government staff people ask the patients to go to their private hospitals so that they can charge them there.

At the end, I will speak about what Mr. Rakesh Sinha pointed out about rare diseases. We have met the hon. Minister several times regarding this issue. A group of parliamentarians has written several letters to him regarding this. There is a rare disease policy, but it is a meaningless policy because you ask for corporate funding. A patient requires crores of rupees to get treated. There are little children who have got little to live but if you give them treatment, they can survive. And, you are asking them to go to the corporate and ask for funding. The only amount that can be

received through the corporate funding is Rs. 1,87,000. I have approached the hon. Prime Minister. You were speaking about the empathy of the Prime Minister. Here in this very House, I took a letter signed by 20 Members of Parliament asking him for an appointment. Give us an appointment so that we can speak about these rare disease patients, who can be helped, and, even when it is such an important and emotional subject, the Prime Minister has not given us time. If time cannot be given for this issue, for what else will we get time?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

DR. FAUZIA KHAN: Many Members of Parliament are asking for this. I urge the hon. Minister to please consider the problems of rare disease patients and help them with the required amount of money so that these little children can be saved by just a little bit of help by the Government. It is not a big amount that we are asking for. Only a hundred crores of rupees are to be spent from the Rashtriya Arogya Nidhi.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude. We are running out of time.

DR. FAUZIA KHAN: Finally, I would conclude my speech by saying that instead of enhancing the fund for health care, we are applying the GST on hospital rooms. I think, doing such a thing is very, very cruel. GST not only on food items but GST also on hospital treatment! I think, the Government must withdraw this decision immediately. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Members, there is a special request by hon. Member, Shrimati Ranjeet Ranjan asking for permission to speak early as there is some emergency and she has to leave. Does the House allow her to take priority in terms of speaking first? Okay. Shrimati Ranjeet Ranjan ji, please speak.

श्रीमती रंजीत रंजन (छत्तीसगढ़) : महोदय, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बिल लेकर आए हैं - 'स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2021', जो 2021 से पेंडिंग है। मैंने प्रो. मनोज झा जी को भी सुना और उनके बाद हमारे सत्ताधारी पक्ष के श्री राकेश सिन्हा जी को भी सुना। एक्चुअली वे राकेश जी नहीं बोल रहे थे, वे तो भाजपा और सत्ताधारी पक्ष को रीप्रेज़ेंट कर रहे थे और उन्होंने वही कहा, जो उनकी सरकार की रणनीति है। मुझे बहुत अफसोस हुआ, चूंकि भाषण-अभिभाषण सदन में तो होते ही हैं, लेकिन सदन के बाहर भी आपकी राजनीति चलती है और सदन के अंदर भी आप लोग राजनीति ही कर रहे होते हैं। भाई साहब, यहां तो पब्लिक देख नहीं रही है, शायद सुन रही होगी।

उपसभाध्यक्ष जी, यह बहुत ही गंभीर विषय है। जिस तरह आत्मरक्षा का संवैधानिक अधिकार होता है, जीवन रक्षा का संवैधानिक अधिकार होता है, निश्चित तौर से बीमारियों से आत्मरक्षा का संवैधानिक अधिकार भी इस देश में होना ही चाहिए, जो नहीं है। भारत की 140 करोड़ जनता में, मेरे ख्याल से 1 या 1.5 प्रतिशत लोग ही ऐसे होंगे, जो पूरी विलासिता के साथ इलाज करवा पाते होंगे, अन्यथा मिडिल क्लास से भी ऊपर, जो अपर मिडिल क्लास है, जब उनको भी कोई बड़ी बीमारी होती है, तो एक बार वे भी कांप जाते हैं। मिडिल क्लास, लोअर क्लास, बीपीएल, एपीएल की तो बात ही हम छोड़ दें। लोगों की पूरी जिंदगी की जो कमाई है, शायद वह कैंसर, किडनी, हेपेटाइटिस-बी, मलेरिया, कालाज़ार जैसी बीमारियों में ही खत्म हो जाती है। टीबी, हार्ट अटैक, लिवर ट्रांसप्लांट जैसी बीमारियों से तो अभी हम लोग ऊपर ही नहीं आ पाए हैं, रेयर डिज़ीज़ तो अभी बाद में आएंगी। आप बहुत बड़ी-बड़ी बातें कह रहे थे, रेयर डिज़ीज़ की बात कह रहे थे, लेकिन मैं फिर से रेयर डिज़ीज़ से नीचे आऊँगी, क्योंकि हम लोग जहां से आते हैं, अभी उनके लिए यहां बात करना चाहते हैं। हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं, जिनको आपके जिले के सदर अस्पताल पर निर्भर रहना पड़ता है, आपकी आयुष्मान भारत योजना पर निर्भर रहना पड़ता है, आपकी स्वास्थ्य बीमा योजना पर निर्भर रहना पड़ता है। आपने 5,00,000 रुपये दिए, फोटो खिंचवाई और बड़े खुश हो गए। राकेश जी ने तो ऐसे कह दिया, जैसे उन्होंने पूरी गंगा पार कर ली हो, जैसे लोग कहते हैं कि हमने गंगा स्नान कर लिया। आपने पूरे 140 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य का संवैधानिक अधिकार दे दिया, पूरे देश के लोग खुश हैं, सारे किसान खुश हैं, गरीब लोग खुश हैं, सब लोगों का इलाज हो रहा है। जिस तरह घर-घर, हर-हर हम जिनका नाम लेते हैं, उसी तरह हर घर में सबका इलाज हो रहा है। राकेश जी, हम यह स्वास्थ्य का अधिकार क्यों लेकर आए? आप मुझे इतना बता दीजिए। जो 5 लाख रुपये का बीमा है, क्या प्राइवेट अस्पताल उसे लेते हैं? पहले 'नहीं' सामने आया, फिर यह आया कि कुछ अस्पताल उन लोगों को लेने लगे हैं, फिर आया ...(**व्यवधान**)..

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please, please.

श्रीमती रंजीत रंजन : लेकिन आप यह जरूर नोट कीजिएगा कि यह हमारी और आपकी बात नहीं है, यह भाषण की बात नहीं है, यह देश के स्वास्थ्य और नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, यह हम लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। प्राइवेट अस्पतालों में यदि कोई व्यक्ति आपका कार्ड लेकर चला जाता है, तो जब तक उसके पूरे पांच लाख रुपये नहीं निकल जाते हैं, तब तक प्राइवेट अस्पताल वाले आपको बाहर निकलने नहीं देते हैं। 5 लाख रुपये के 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख या 15 लाख रुपये बनते हैं। हमारे देश में एक संस्कार बना हुआ है, जब तक हम और आप जैसे लोग 'एम्स' में फोन नहीं करते, सफदरजंग अस्पताल में फोन नहीं करते या सदर अस्पताल में फोन नहीं करते, तब तक आम आदमी का इलाज नहीं होता है, क्या उनका इलाज होता है? * पेशेन्ट तो देश का है। ...(**व्यवधान**)..पेशेन्ट तो देश का है, आप प्लीज़ सुनिये। पेशेन्ट तो देश का है।

श्री राकेश सिन्हा : मेरा प्वांइट ऑफ ऑर्डर है ...(**व्यवधान**)..

* Expunged as ordered by the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): There is a point of order. ...*(Interruptions)*... Under which rule?

SHRI RAKESH SINHA (Nominated): Under Rule 238. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती रंजीत रंजन : देश में कौन सा ...(**व्यवधान**).. वाइस चेयरमैन साहब, कौन सा रूल है?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): One second, please. There is a point or order. ...*(Interruptions)*... Under which rule?

SHRI RAKESH SINHA: Under Rule 238. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI RANJEET RANJAN: You should respect. ...*(Interruptions)*...

SHRI SYED NASIR HUSSAIN (Karnataka): Sir, this is not allowed. ...*(Interruptions)*..

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): One second, please. ...*(Interruptions)*... एक मिनट में बात खत्म हो जाएगी। आपका प्वाइंट ऑफ ऑर्डर क्या है?

श्री राकेश सिन्हा : हिन्दुस्तान के चिकित्सकों पर राजनीति करने का आरोप लगाना एक तरह से उनका अपमान है। ...(**व्यवधान**)..

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you, thank you. Please, Rakesh ji. I have allowed you.

श्री राकेश सिन्हा : सर, इसे प्रोसीडिंग्स से निकाला जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): We will examine it. ...*(Interruptions)*... Please continue, Ranjeet Ranjan ji. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती रंजीत रंजन : थैंक यू, उपसभाध्यक्ष जी। अभी मैं आपके सदर अस्पताल, जिला अस्पताल और शहरों के अस्पतालों पर नहीं आई हूं। वहां के जो हालात हैं, आप 'आयुष्मान' की बात कर रहे हैं, मैंने आपको रिएलिटी बताई है। आप मोदी साहब से जरूर बात करें, वे हमारे देश के प्रधान मंत्री हैं। आप प्राइवेट अस्पतालों में सर्दी, जुकाम के लिए जाइये, वे कहते हैं कि आपको किडनी की बीमारी है, आपको कैंसर हो सकता है, आपको हेपेटाइटिस-बी हो सकता है, इसलिए धीरे-धीरे सारे टैस्ट्स कराते हैं, जब तक कि उसके पांच लाख रुपये खत्म नहीं हो जाते। यह भी शायद आपका * है, सत्ता का * है, जिनके साथ आपने इनको टैग किया हुआ है, जिन एजेन्सीज़ के साथ टैग किया हुआ है, उनके साथ आपका क्या * है, यह परसेंटेज आप जानते होंगे, मैं आपको रिएलिटी बता रही हूं।

---

* Expunged as ordered by the Chair.

महोदय, आप सदर अस्पताल की बात कह रहे हैं, आप भाषणों में बोलिये कि किडनी का जो ट्रांसप्लान्ट होता है, जो डायलिसिस होता है, उसकी सुविधा आपने सरकारी अस्पतालों में दी है। आपने कैंसर की जो कीमोथेरेपी होती है, उसकी फैसिलिटी दी है।

महोदय, मैं दावा करती हूं कि आप बिहार, बंगाल, हरियाणा या पंजाब जैसे प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक ब्लड का टैस्ट करा दीजिए, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। इन स्थानों पर एक भी लैब नहीं है, ब्लड टैस्ट की सुविधा नहीं है, बर्न विभाग नहीं है, अल्ट्रासोनोग्राफी की सुविधा नहीं है ...(**व्यवधान**).. आप सुनिये ...(**व्यवधान**)..

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : प्लीज़, जांगड़ा जी, आप बैठिये। ...(**व्यवधान**).. माननीय कान्ता जी, प्लीज़ बैठिये। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती रंजीत रंजन : उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपको आगाह कर रही हूँ, जो विपक्ष का काम होता है। सत्ता पक्ष अगर काम कर रहा है, आपने सुविधा दी है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है **...(व्यवधान)...** आप सुनिए। **...(व्यवधान)...** नहीं किया। **...(व्यवधान)...** नहीं किया। **...(व्यवधान)...** मान लिया कि हमने नहीं किया। आप अपने 8 साल का ब्यौरा दीजिए। **...(व्यवधान)...** मैं 8 साल का ब्यौरा माँग रही हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Kindly address the Chair. **...** (*Interruptions*)**...** आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्रीमती रंजीत रंजन : हमने 30,000 रुपये दिये थे **...(व्यवधान)...** सदर अस्पताल के लिए। **...** (**व्यवधान**)**...**

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): No cross-talk, please.

श्रीमती रंजीत रंजन : हमने 30,000 को सवा लाख किया था। वह सरकारी अस्पताल के लिए था। आप बहुत बड़ी अमीर पार्टी के हैं, क्योंकि आपने नोटबंदी की, पैसा अर्न किया, पाँच लाख रुपये दिये। आप फिर पाँच लाख रुपये उन कम्पनीज़ को दे रहे हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ।

सर, मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहती हूँ कि देश के स्वास्थ्य के हालात क्या हैं। अभी मनोज झा जी कोरोना की बात कर रहे थे। हमें दुख होता है। आप लोगों को, मेरी कुछ बहनों को हँसी आ रही थी। मुझे लगता है कि अगल-बगल से एक दिन में 200 फोन कॉल्स, 300 फोन कॉल्स हम लोग अटेंड कर रहे थे। लोग कहते थे कि मैडम, अगर डेढ़ लाख का भी ऑक्सीजन सिलेंडर मिले, तो प्लीज़ दिलवा दीजिए, क्योंकि हमें किसी की जान बचानी है। रेमडेसिविर 15,000 रुपये में मिल रही थी। मैं आपको एक बात और कहूँगी। वह 40,000 में भी मिली, जो 15,000 से स्टार्ट हुई थी। आप अभी रेयर डिज़ीज़ की बात कर रहे थे। उपसभाध्यक्ष जी, पहले मैं ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करती हूँ। आपने कोरोना में जो ऑक्सीजन सिलेंडर डेढ़ लाख में दिया, ये जिन कोरोना पेशेंट्स को यूज़ कराये गये **...(व्यवधान)...** आप मेरी बात सुनिए। **...(व्यवधान)...** यह बहुत सेंसिटिव मामला है। **...(व्यवधान)...** उपसभाध्यक्ष जी **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): No cross-talk, please. ...(*Interruptions*)... No cross-talk, please.

श्रीमती रंजीत रंजन : उपसभाध्यक्ष जी, जिन व्यक्तियों को, जिन कोरोना पेशेंट्स को ये यूज़ कराये गये, आज उन लोगों को - आपको भी पता होगा 'ब्लैक फंगस' नामक एक बीमारी आयी थी। मेरे घर में मेरी ननद का पति है, जो आपके बिजली विभाग में जॉब में है। वह पटना से आकर यहाँ पर इलाज करा रहा है और अभी तक दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में उसके 15 लाख खर्च हो चुके हैं। उसके 7 ऑपरेशंस हो चुके हैं और डॉक्टर ने बोला कि फंगस कैसे हुआ। वह कोरोना के कारण नहीं हुआ था। ऑक्सीजन सिलेंडर में जो पानी था, वह लोगों को देने के लिए नहीं था, बल्कि वह फैक्टरी के यूज़ के लिए था। वह मिनरल नहीं था, फिल्टर्ड नहीं था और आपने आनन-फानन में लोगों को उस ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन दी, जिसका परिणाम यह हुआ कि कइयों की जान गयी और कइयों ने अपनी आँख खोयी, कइयों ने अपने ब्रेन में ट्यूमर लिया, कइयों ने अपनी नाक में प्रॉब्लम ली ...(**व्यवधान**)... कइयों का जबड़ा ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please, no discussion. ...(*Interruptions*)... No cross-talk, please. ...(*Interruptions*)... मैं दोनों तरफ के लोगों को कह रहा हूँ प्लीज़।

श्रीमती रंजीत रंजन : उपसभाध्यक्ष जी, मैं क्वोट कर रही हूँ। अगर किसी को आपत्ति है तो डॉक्टर का मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लाकर सभा पटल पर रखने का माद्दा भी हम लोग रखते हैं। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**डा. सस्मित पात्रा**) : आप कन्क्लूड करें। ...(**व्यवधान**)... ऑनरेबल मेम्बर, अब आप कन्क्लूड करें।

श्रीमती रंजीत रंजन : उपसभाध्यक्ष जी, दूसरी बात यह है कि अभी बहुत बढ़-चढ़ कर भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे राकेश जी बोल रहे थे कि हमने कोरोना काल में यह किया, हमने कोरोना काल में वह किया। पूरा देश चाहता था कि जो लोग कोरोना से व्यथित थे, जो लोग कोरोना से पीड़ित थे, देश उनको सुविधा प्रदान करता, लेकिन यहाँ तो बोलियाँ लग रही थीं। मुझे गर्व है कि दिल्ली के एम्स में, सफदरजंग अस्पताल में, जितने अस्पताल कांग्रेस ने बनाये थे, उनमें ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। यह फैक्ट है। ...(**व्यवधान**)... यह फैक्ट है। ...(**व्यवधान**)... उपसभाध्यक्ष जी, मैं क्वोट कर रही हूँ। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please maintain silence. ...(*Interruptions*)...

श्रीमती रंजीत रंजन : एम्स के एक भी डॉक्टर ने या एक भी पेशेंट ने ...(**व्यवधान**)... उनके पास पेशेंट्स के लिए जितने बेड्स थे ...(**व्यवधान**)... जितने उनके पास बेड्स थे, उतने ही पेशेंट्स उन्होंने लिए। एक भी ज्यादा नहीं लिया। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : आप कन्क्लूड करें। **...(व्यवधान)...** ऑनरेबल मेम्बर, अब आप कन्क्लूड करें।

श्रीमती रंजीत रंजन : प्लीज़, प्लीज़। मैं दो-तीन मिनट और लूँगी। यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है। **...(व्यवधान)...** सर, जितने भी प्राइवेट अस्पताल थे, जितने भी छोटे अस्पताल थे, जिन्होंने दुकान खोली हुई थी, सरकार उन पर लगाम लगाने में, ऑक्सीजन की कालाबाज़ारी रोकने में और रेमडेसिविर की कालाबाज़ारी रोकने में फेल थी। सर, क्या कोरोना की दवाई थी? **...(व्यवधान)...** सर, क्या यह सदन और प्रधान मंत्री बतायेंगे कि कोरोना की दवाई थी? अगर नहीं थी, तो डॉक्टर एक-एक आदमी से 20-20 लाख रुपए लेकर करोड़ों का इलाज किस तरह से कर रहे थे? ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please. *...(Interruptions)...*

श्रीमती रंजीत रंजन : सर, मैं डॉक्टर का नाम नहीं बताऊँगी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि नाम नहीं बताना। जब उन्हें कोरोना हुआ, तब वहाँ के अस्पताल ने उनसे 30 लाख रुपए लिए, क्योंकि उनका इंश्योरेंस था। ...(**व्यवधान**)... सर, यह कौन सा खेल चल रहा है? ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude. *...(Interruptions)...* Hon. Member, please conclude. *...(Interruptions)...*

श्रीमती रंजीत रंजन : महोदय, हम चाहते हैं कि इस देश में स्वास्थ्य का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि हम खासकर अपने गरीब तबके के लोगों को, गाँव के लोगों को, बीपीएल को, एपीएल को, सर्विस क्लास के लोगों को जानवर की तरह ट्रीट करते हैं। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : आप कन्क्लूड करिए। ...(**व्यवधान**)... आप कन्क्लूड करिए। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती रंजीत रंजन : सर, दो मिनट और दे दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): No, no. *...(Interruptions)...* आप कन्क्लूड करिए। ...(**व्यवधान**)... We will examine. *...(Interruptions)...* We will examine.

श्रीमती रंजीत रंजन : सर, आप राम मनोहर लोहिया अस्पताल चले जाइए, आप एम्स चले जाइए ...(**व्यवधान**)... आप बिहार चले जाइए ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : आप कन्क्लूड कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती रंजीत रंजन : सर, मैं कन्क्लूड कर रही हूँ। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): You have 30 seconds. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती रंजीत रंजन : माननीय सदस्या रजनी पाटिल जी और फौजिया खान जी गंदगी की बात कर रही थीं। ...(**व्यवधान**)... सर, हम लोग प्रतिनिधि रहे हैं, मैंने दो बार लोक सभा का प्रतिनिधित्व किया है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : आप कन्क्लूड कीजिए। ...(**व्यवधान**)... आप कन्क्लूड कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती रंजीत रंजन : अगर आप सदर अस्पताल में एक घंटा खड़े हो गए और बिना बीमारी लिए हुए गए आ गए, तो मैं अपना नाम बदल लूँगी। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. ...*(Interruptions)*... Please conclude. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती रंजीत रंजन : सर, प्लीज़ दो मिनट दे दीजिए। ...(**व्यवधान**)... मैं किसी पर एलीगेशन नहीं लगा रही हूँ। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude. ...*(Interruptions)*... आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़, कन्क्लूड कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

SHRIMATI RANJEET RANJAN: Sir, please two minutes. ...*(Interruptions)*... मैं किसी पर तोहमत नहीं लगा रही हूँ, बल्कि देश के हालात बता रही हूँ। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Last 30 seconds. ...*(Interruptions)*... आप कन्क्लूड कीजिए । ...(**व्यवधान**)... Silence please. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती रंजीत रंजन : सर, मैं उदाहरण देती हूँ। ...(**व्यवधान**)... हमारे जैसे गाँव का बच्चा, जिसका पूरा शरीर जल गया ...(**व्यवधान**)... आपको हँसी क्यों आ रही है? ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : प्लीज़, आप चेयर को एड्रेस कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती रंजीत रंजन : वह मेरा बेटा नहीं है, गाँव का बेटा है। ...(**व्यवधान**)... मैं गाँव के बेटे की बात कर रही हूँ। ...(**व्यवधान**)... मेरे बेटा हो, तो पैसे देकर करा लूँगी। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Shrimati Ranjan, please address the Chair. ...*(Interruptions)*... Thank you. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती रंजीत रंजन : सर, उसका होंठ गले तक आ गया, कान पीठ तक आ गया। ...(**व्यवधान**)... वह अपना इलाज नहीं करा पाया, क्योंकि सदर अस्पताल, जिला अस्पताल, कहीं पर कोई फैसिलिटी नहीं थी। ...(**व्यवधान**)... उसे गाँव में ही रखकर इलाज कराया गया। ...(**व्यवधान**)... उसकी स्किन उतरकर पेट तक सटी हुई थी। ...(**व्यवधान**)... क्या यह रेअर नहीं है? ...(**व्यवधान**)... मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में स्वास्थ्य के हालात बद से बदतर हैं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : आप कन्क्लूड कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती रंजीत रंजन : सर, सिर्फ भाषणों से काम नहीं होगा, सिर्फ उद्घाटन करने से काम नहीं होगा, बल्कि नीयत और नीति, दोनों सही होनी चाहिए। ...(**व्यवधान**)... एक तरफ आप कह रहे हैं कि इलाज हो रहा है ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. I will have to move on. *...(Interruptions)...* मैंने आपको काफी समय दे दिया है। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती रंजीत रंजन : सर, मैं सिर्फ एक आंकड़ा बताना चाहती हूँ। ...(**व्यवधान**)... हजार लोगों पर एक डॉक्टर है। ...(**व्यवधान**)... आप कह रहे हैं कि हम इलाज कर रहे हैं! ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : प्लीज़ 30 सेकंड में कन्क्लूड कीजिए, otherwise I will have to move on.

श्रीमती रंजीत रंजन : सर, मैं एक और प्वाइंट रखना चाहूँगी। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : नहीं, अब आपको कन्क्लूड करना पड़ेगा। ...(व्यवधान)... I am sorry, I will have to move on. *...(Interruptions)...* No, no. *...(Interruptions)...* मैं आपको काफी समय दे चुका हूँ। ...(**व्यवधान**)...

SHRIMATI RANJEET RANJAN: Sir, please, one minute. *...(Interruptions)...*

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : आप कन्क्लूड कर रही हैं? ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती रंजीत रंजन : सर, मैं कन्क्लूड कर रही हूँ। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : आप कन्क्लूड कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती रंजीत रंजन : सर, 189 कंट्रीज़ में हमारे देश का नंबर 179 पर है। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, Dr. Anil Sukhdeorao Bonde. ...*(Interruptions)*... I will have to move on. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती रंजीत रंजन: हमारा जो जीडीपी है, उससे आगे भूटान और श्रीलंका खड़े हैं। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I will have to move on. ...*(Interruptions)* ... Thank you. ...*(Interruptions)*... I am moving on. ...*(Interruptions)*... Thank you. ...*(Interruptions)*... आपका समय खत्म हो चुका है। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती रंजीत रंजन : सर, मैं आग्रह करती हूँ कि स्वास्थ्य का अधिकार सबको मिलना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, Dr. Anil Sukhdeorao Bonde.

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज मनोज कुमार झा जी ने ...(**व्यवधान**)...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO (Uttar Pradesh): Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, I am on a point of order. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Under which rule? ...*(Interruptions)*... One second. ...*(Interruptions)*... I have two points of order. ...*(Interruptions)*... I will take the first point of order and then yours. ...*(Interruptions)*... Under which rule? ...*(Interruptions)*... I will. I have recognized. ...*(Interruptions)*... Under which rule? ...*(Interruptions)*...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, it is under Rule 238 (2). ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Silence please. ...*(Interruptions)*...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, it is under Rule 238 (2) - 'making a personal charge against a member'. ...*(Interruptions)*... I think, while speaking, Dr. Fauzia Khan has made certain accusations against the hon. Prime Minister. ...*(Interruptions)*... I think, this is not acceptable. ...*(Interruptions)*... This must be expunged from the records. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): We will examine. ...*(Interruptions)*...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: It is in the nature of an allegation. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): We will examine. ...*(Interruptions)*...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: The Prime Minister is also a member of the Council of Ministers. ...*(Interruptions)*... I think, the allegation must be removed from the records. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): We will examine. ...*(Interruptions)*... Okay, now, I have the second point of order. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... Please ...*(Interruptions)*... रंजीत जी, प्लीज़ अपनी जगह लीजिए। ...(**व्यवधान**)... I have the second point of order. ...*(Interruptions)*... Yes.

DR. V. SIVADASAN: My point of order here is....

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Under which rule?

DR. V. SIVADASAN: Sir, it is Rule 239.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Under Rule 239.

DR. V. SIVADASAN: While the Member was speaking here, the other Members from the Ruling Benches, the Treasury Benches, were putting questions to the Member. ...*(Interruptions)*... That is very wrong. ...*(Interruptions)*... Clearly, it is here, "When, for the purposes of explanation during discussion or for any other sufficient reason, any Member has occasion to ask a question of another Member on any matter then under the consideration of the Council, he shall ask the question through the Chairman." ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Through the Chairman. ...*(Interruptions)*... I get it. ...*(Interruptions)*... Through the Chairman. Understood. ...*(Interruptions)*... Understood. ...*(Interruptions)*... Through the Chairman. ...*(Interruptions)*... Through the Chairman. ...*(Interruptions)*...

DR. V. SIVADASAN: But, they clearly violate this, you please take action against them. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. Point taken. Now, Dr. Anil Bonde. Yes, please. Thank you. ...*(Interruptions)*... Thank you, moving on.

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे : आज प्रो. मनोज कुमार झा, सांसद ने हेल्थ के ऊपर जो चर्चा रखी है, उसमें मैं सम्मिलित हो रहा हूँ। हेल्थ की डेफिनेशन यह दी जाती है कि वैल-बीइंग होनी चाहिए। That should be the mental and physical well being, emotional and spiritual well-being. डिज़ीज़ के बारे में कहा जाता है कि जिसमें ईज़ न हो - डिस-ईज़, लेकिन आज मुझे इस सदन में दिखा कि कुछ लोगों को असत्य बोलने की बीमारी भी लग सकती है। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): No; I am not allowing. ...*(Interruptions)*... Is it a point of order? ...*(Interruptions)*... Is it a point of order? ... *(Interruptions)* ... Please address the Chair. ...*(Interruptions)*... Address the Chair. ...*(Interruptions)*...

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे : गलत जानकारी भी हो सकती है, जिसको कुछ लोग असत्य भी बोलते हैं। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*...

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे : अगर ऐसी बीमारी रही, तो उसका इलाज भी बहुत जल्दी करना जरूरी है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कोविड का जो पीरियड था, वह सबके लिए एक बड़ा टैस्ट था। चाहे वे डॉक्टर्स हों, हेल्थ पर्सनेल्स हों, पॉलिटिशियंस हों या एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, इन सबके लिए वह एक बहुत बड़ा टैस्ट था, क्योंकि सौ साल के बाद पैन्डेमिक आता है। एन्डेमिक, एपिडेमिक बहुत बार आता है, लेकिन आपको पता है कि 1820 में पैन्डेमिक आया था, 1920 में पैन्डेमिक आया था और अब 2020 में पैन्डेमिक आया था। पैन्डेमिक आने के बाद पूरी दुनिया के देश गड़बड़ा जाते हैं। किसी देश की चाहे कितनी भी अच्छी हेल्थकेयर फैसिलिटी हो, ऐसे देश भी गड़बड़ा जाते हैं। यू.के. में अच्छी हेल्थकेयर फैसिलिटी थी, लेकिन वहाँ भी वेंटिलेटर्स नहीं मिले, वहाँ भी एडमिशन के लिए लाइन लगती थी। इसी तरह, यू.एस.ए. में भी यही परिस्थिति थी। इनिशियल प्रॉब्लम तो यह थी कि डॉक्टर्स को भी एग्ज़ैक्ट इन्फ़ॉर्मेशन नहीं थी कि इसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट देना है। जब कन्फ्यूज़न ज्यादा रहता है, ऐसे वक्त में कंट्री को जो लीड कर रहा है, डब्ल्यूएचओ जो गाइडलाइन दे रहा है या यहाँ की आरोग्य संस्थाएँ जो गाइडलाइन दे रही हैं, उनको अच्छे से नीचे तक फॉलो-अप कराने का काम जो हेल्थ सिस्टम करता है, अगर वह सक्सेसफुल रहा, तो डेफिनेट्ली लोगों को हेल्थ का राइट मिल गया, ऐसा हम बोल सकते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण इलाके में रहता हूँ और मेरा ऐसा अनुभव है कि पहले एपिसोड और दूसरे एपिसोड में थोड़ा फर्क था। पहले में इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन हमारे आदरणीय पंत प्रधान नरेन्द्र मोदी जी द्वारा आखिरी पायदान तक यह मैसेज पहुँचाया गया था कि आपको सेफ डिस्टेंस रखना है, आपको हाथ धोने हैं, अगर आपने मास्क नहीं लगाया, तो कोरोना

होने की ज्यादा संभावना है। यह मैसेज आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी सेविकाएँ और नीचे के हेल्थ पर्सनेल्स घर-घर जाकर दे रहे थे। यह जो डोर टू डोर सर्विस है, हेल्थ में यही सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद, उससे प्रिवेंशन के लिए माननीय पंत प्रधान जी ने बार-बार यह कहा कि हम इन्डिजनस वैक्सीन बनाएँगे। हमारे यहां हम वैक्सीन बनाएंगे।

[**उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी)** *पीठासीन हुईं*]

हम ऑक्सफोर्ड से मदद लेकर वैक्सीन बनाएंगे। कोवैक्सीन बनी, कोविशील्ड बनी, पुणे में वैक्सीन बनी। उस वक्त वैक्सीन बनने के बाद मुझे इसलिए दुख हुआ कि भारत में कुछ लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे कि यह मोदी वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। उन लोगों को भारत की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि एक बड़े नेता ने बोला कि यह मोदी वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे, तब भारत का 20 परसेंट तबका ऐसा था, जिन्होंने सोचा कि यह मोदी जी की वैक्सीन है, हम इसे नहीं लगाएंगे। पैन्डेमिक में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिन लोगों का इन्फ्लुएंस रहता है, उन लोगों का पूरे देश के साथ में चलना ज़रूरी होता है, यानी जो नेता हैं, जो अभिनेता हैं, जिन्हें हम की-पर्सन बोल सकते हैं, उनको सबसे पहले वैक्सीन लगती है तो नीचे वाले लोगों को भी लगता है कि वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। आज हम सबको गर्व होना चाहिए, चाहे वे विरोधी हों या अन्य कोई भी सदस्य हों, कि ज्यादातर सभी लोगों को, चाहे वे 60 साल के ऊपर की उम्र के हों, चाहे 18 साल के ऊपर की उम्र के हों, वैक्सीन की दो डोज़ लग चुकी हैं। आज हम बूस्टर डोज़ की तरफ बड़ी ताकत से जा रहे हैं। बूस्टर के बारे में भी संभ्रम फैलाने की कोशिश की गई। अब ऐसे वक्त राइट टू हेल्थ - जब आखिरी आदमी वैक्सीन के बारे में जानता है, कोविड के बारे में जानता है, तब मैं समझता हूं कि हम - एक्चुअली राइट टू हेल्थ कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हम प्रार्थना ही करते हैं। *'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः'।* सर्वे सन्तु निरामयाः का अर्थ है कि सभी रोगमुक्त रहें। यह तो हमारी प्रार्थना ही है। यह कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है।

प्रो. मनोज कुमार झा : आप इसको संविधान में ले आइए।

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे : यह सही बात है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि संविधान में हमारे मूलभूत अधिकार हैं। हमारे संतों ने भी बोला है। हमारे संत गाडगे महाराज थे, उन्होंने बोला है *'भुकेल्यांना अन्न द्या, तहानलेल्यांना पाणी द्या, आजारी असलेल्यांना औषध द्या'।* वही मोदी जी कर रहे हैं। वे जनऔषधि में क्या कर रहे हैं! आपको पता है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़िज़ हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, एक-एक दिन की दवाई सौ रुपये से अधिक की होती है, वह सौ रुपये की दवाई 30-40 रुपये में मिले या 10 रुपये में मिले, तो 300 रुपये महीने में हाइपरटेंशन कंट्रोल कर सकते हैं। यह बात ख्याल में क्यों नहीं आती?

मैं 'आयुष्मान भारत योजना' के बारे में बताता हूं। एक्चुअली हेल्थ जो सब्जेक्ट है, यह स्टेट के अंतर्गत आता है। यह कन्करेंट सब्जेक्ट नहीं है। वैसे तो यह योजना राज्य सरकारों को चलानी चाहिए। तमिलनाडु ने पहली बार शुरू की थी, महाराष्ट्र में भी शुरू की गई थी, वह राजीव गांधी जी के नाम से शुरू की गई थी, फिर महात्मा ज्योतिबा फुले जी के नाम से देवेन्द्र फडणवीस जी ने बहुत अच्छे तरीके से चलाई, बाकी अन्य स्टेट्स ने भी चलाई, लेकिन वह डेढ़ लाख रुपये तक की थी, उसके बाद अगर पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज देना है तो 'आयुष्मान भारत योजना'

के माध्यम से कैंसर के पेशेंट भी अपना इलाज अच्छे से करा सकते हैं, कोरोनरी बाईपास का पेशेंट हो या अन्य पेशेंट्स हो, ये सब पेशेंट्स अच्छी तरह से रियायत पा सकते हैं। यह कब महसूस होगा, जब हम उन पेशेंट्स के घर में उनके रिलेटिव्स की तरह जाएंगे। पेशेंट को किडनी ट्रान्सप्लांट करवाना है। वह एम्स में जाता है और 'आयुष्मान भारत योजना' का लाभ लेता है, उसका किडनी ट्रान्सप्लांट होता है, उस वक्त वह कोई पोलिटिक्स नहीं सोचता है, वह पंत प्रधान नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देता है।

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी) : अनिल जी, आप कन्क्लूड कीजिए।

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे : मैं कन्क्लूड करता हूं। उपसभाध्यक्ष महोदया, यह जो हेल्थ सब्जेक्ट है, यह कन्करेंट लिस्ट में आना चाहिए। यह सिर्फ राइट टू हेल्थ नहीं है, ...(**समय की घंटी**)... क्योंकि इसमें स्पिरिचुअल, मेन्टल, इमोशनल हेल्थ भी इन्क्लूडेड है, इसमें सरकार की तरफ से एकाध कम्प्रीहेन्सिव पब्लिक हेल्थ लेजिस्लेशन बना तो वह बहुत स्वागत योग्य रहेगा। ...(**व्यवधान**)... दूसरी बात यह है कि इसकी फंडिंग के लिए भी जैसे मोदी जी ने कोरोना के काल में किया, वैसे ही बहुत बड़े-बड़े लोग हैं, जो हेल्थ के लिए फंड देना चाहते हैं। एक ऐसी कंक्रीट डेज़िग्नेटेड ऑटोनॉमस एजेंसी रहनी चाहिए कि जो गरीबों को शासन के मार्फत मदद करे। आज आपने अच्छी चर्चा निकाली, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और मेरे शब्दों को विराम देता हूं। जय हिन्द!

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं हृदय से आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं मनोज झा जी का भी आभारी हूं कि वे राइट टू हेल्थ का महत्वपूर्ण बिल लेकर आए। मैडम, इस देश में जब यह महसूस किया गया कि लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, भूख के कारण मौत हो रही है, तो राइट टू फूड का बिल पास किया गया। जब यह महसूस हुआ कि देश शिक्षा के क्षेत्र में लगातार पिछड़ता जा रहा है, लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो राइट टू एजुकेशन का बिल पास हुआ। आज हम ऐसे हालात में खड़े हैं, जहां पर न सिर्फ हिन्दुस्तान, बल्कि पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से अभी भी जूझ रही है। हिन्दुस्तान में भी कोरोना के कारण लाखों लोगों की मौत हुई। हम लोगों ने देखा कि उस कोरोना के कारण जो गरीब लोग थे, किसान थे, मज़दूर थे, वे सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल चलकर अपने घर गए। जहां वे रहते थे, वहां इलाज नहीं मिल पाया। हमने देखा कि जब वे चलते-चलते थक गए और रेल की पटरियों पर बैठकर खाना खाने लगे, तब उन्हें नींद आ गई और रेल उनके ऊपर से गुजर गई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई, लेकिन उनको इलाज नहीं मिल पाया, वे घर नहीं पहुंच पाए।

महोदय, हम लोगों के लिए स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण विषय है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं और मैं इनका सम्मान करता हूं। पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक बड़ी पहल की और ऐसा करना चाहिए। बाकी मंत्रियों को भी निश्चित रूप से इनसे सीख लेनी चाहिए। ये स्वयं एक सामान्य नागरिक बनकर जब एम्स अस्पताल में गए, तो इनको वहां पर रोक लिया गया, इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। ये खुद रूबरू हुए कि वास्तव में अस्पताल में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना एक मरीज को या उसके साथ के लोगों को करना पड़ता है। इसलिए मैं यह बिल्कुल नहीं कहूंगा कि स्वास्थ्य का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह कहना

गलत होगा। शिक्षा का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह कहना गलत होगा, क्योंकि राजनीति ही तो तय करती है कि स्वास्थ्य पर कितना बजट होगा, शिक्षा पर कितना बजट होगा, सड़क पर कितना होगा, पानी पर कितना होगा, बिजली पर कितना होगा, इसलिए यह राजनीतिक मुद्दा है। अगर आज़ादी के 75 साल बाद भी सफदरजंग अस्पताल के सामने एक महिला जो प्रसव से पीड़ित थी, उसको अपने बच्चे की डिलीवरी लोगों की घेराबंदी में करनी पड़ती है, तो मैं समझता हूं कि यह सदन के सभी सदस्यों के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, हम सब के लिए शर्मिंदगी की बात है। हम सबको सोचने की आवश्यकता है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कहां पहुंच गई है? पिछले दिनों महोबा के अंदर एक खबर आई। वह दिल दहला देने वाली खबर थी। आप भी सुनेंगी, तो आपकी रूह कांप जाएगी। एक मासूम बच्चा महोबा के अस्पताल में एडमिट था, जिसको चींटियों ने खाकर मार दिया। यदि मैं गलत कह रहा हूं, तो मेरे ऊपर कार्रवाई कीजिएगा। इस प्रकार की स्वास्थ्य व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं। जब केन्द्र का बजट आता है, तो हम पढ़ते हैं कि पूंजीपतियों का कॉरपोरेट टैक्ट 30 परसेंट से घटाकर 22 परसेंट कर दिया। 1 लाख 45 हज़ार करोड़ रुपये का देश के बजट को घाटा हुआ। जब हम स्वास्थ्य का बजट पढ़ते हैं, तो केवल दो परसेंट के बारे में पढ़ते हैं।

5.00 P.M.

यह स्वास्थ्य को लेकर हमारी चिंता है! हम देश में स्वास्थ्य का यह विकास करना चाहते हैं! हमारे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य यहां बार-बार कह रहे हैं कि यह तो राज्य का विषय है, यह राज्य का विषय है, यह राज्य का विषय है। ...(**समय की घंटी**)... मैं आपसे कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, तो यह बता दीजिए कि राज्य सरकारों को गिराना किसका विषय है? विधायकों की खरीद फरोख्त करना किसका विषय है? ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी) : प्लीज़, आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री संजय सिंह : मंत्रियों को पद प्रलोभन देकर सरकारों को गिराना किसका विषय है? यह आप बता दीजिए।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी) : माननीय सदस्य, आपकी चर्चा जारी रहेगी।

श्री संजय सिंह : मैडम, सबको मौका दिया गया है। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी) : माननीय सदस्य, आपकी चर्चा जारी रहेगी। आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री संजय सिंह : मैडम, मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली में एक सरकार चल रही है। ... (**समय की घंटी**) ... उस सरकार के मुख्य मंत्री केजरीवाल जी ने शिक्षा का बजट 14 प्रतिशत रखा है। ...(**समय की घंटी**) ... मैडम, सबको बोलने का मौका मिला है और मुझे भी अपनी बात कहने का मौका दिया जाए।

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी) : आपको अगली डेट पर बोलने का मौका मिलेगा। प्लीज़, आप वाइंड अप कीजिए।

श्री संजय सिंह : मैं दिल्ली के बारे में बता रहा हूं। दिल्ली का स्वास्थ्य बजट 14 परसेंट है। ...(**व्यवधान**)... हमने 520 मोहल्ला क्लीनिक्स बनाए हैं। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी) : स्पेशल मेंशन्स। माननीय सदस्य आपका ही स्पेशल मेन्शन है।

श्री संजय सिंह : ठीक है, मैं अपनी स्पीच बाद में कन्टिन्यू करूंगा।

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी) : हाउस इसके बाद भी चलेगा और चर्चा जारी रहेगी। स्पेशल मेन्शन - श्री संजय सिंह जी।

SPECIAL MENTIONS

Need to review the recent hike in rate of Goods and Services Tax (GST)

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) **:** महोदय, हमारे देश में महंगाई हर रोज नया आसमान छू रही है। इस बढ़ती महंगाई ने आम आदमी के जीवन को हिला कर रख दिया है। महोदय, आज़ादी के बाद से आज पहली बार ऐसा हुआ है कि अब लोगों को आटा से लेकर अस्पतालों के कमरे, स्याही, दाह संस्कार और आम आदमी की जरूरत की हर चीज़ पर 5 परसेंट से लेकर 18 परसेंट तक टैक्स देना होगा। सरकार दाल, दही, लस्सी और चावल सभी पर टैक्स लगा रही है। यहां तक कि अब लोगों को अपने ही बचत खाते से पैसे निकालने पर टैक्स देना होगा। इस बेतहाशा कर वृद्धि से आम लोगों का जीविकोपार्जन और बरबाद हो जाएगा। पहले से ही देश में लगभग 19 करोड़ लोग हर रात खाली पेट सोने को मजबूर हैं और देश में पांच साल से कम उम्र के हर दिन लगभग 4,500 बच्चे भूख और कुपोषण के कारण मर रहे हैं। अकेले भूख के कारण हर साल तीन लाख से अधिक बच्चों की मौतें हो रही हैं जबकि देश हित में असली कदम यह होता कि गरीबों को महंगाई से राहत दिलाने का प्रयास किया जाता और जिनके पास अधिक धन-दौलत है, उनसे टैक्स की वसूली की जाती। सरकार का यह कदम देश में भुखमरी, कुपोषण और गरीबी को बढ़ावा देगा और लोगों को आटा-चावल के लिए भी तरसा देगा। उपरोक्त विकट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस फैसले पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है।

SHRI JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.